चौथा संसार, इन्दौर
13 MAY 2010

स्वर्णिम म.प्र से विपक्ष का विरोध

यह अगर मान लें कि भाजपा सरकार स्वर्णिम म.प्र. के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं करने वाली । यह भी मान लें कि यह भाजपा सरकार का एक राजनीतिक शिगूफा है । तब भी कांग्रेस की यह जिम्मेदारी थी कि वह सदन के भीतर और बाहर उस पर बहस करती और यह साबित करती कि किस तरह सरकार लोगों को या जनता को भरमा रही है । लेकिन यदि विपक्ष यह नहीं कर पाया तो इसका मतलब साफ है कि वह इस मुद्दे पर विरोध लायक मुद्दो ही नहीं जुटा पा रहा । इसे यूं भी कह सकते है कि विपक्ष के पास इस समय अपने प्रदेश को स्वर्णिम बनाने लायक कोई मुद्दे ,कोई सुझाव ही नहीं है ?

लोकतंत्र में लोकतंत्र का जितना मखौल उडाया जाता है उतना निश्चित ही किसी अन्य तंत्र में नहीं उडाया जा सकता । यहां तमाम विरोधी दल किसी मामूली से मुद्दे पर भी आसमान सिर पर उठा लेते हैं और बेशकीमती ,जनहित से जुडे मुद्दों पर आंखें मूंदे बैठे रहते हैं । ऐसा ही इन दिनों वे मध्यप्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कर रहे हैं । स्वर्णिम म..प्र. के निर्माण पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित इस विशेष अधिवेशन में भाग न लेकर मुट्ठी भर विपक्ष अपने कौन-से अहम को शांत कर रहा है यह तो वही जाने,लेकिन इतना तय है कि उसने सत्र का बहिष्कार कर यह जता दिया कि वह विरोध का केवल प्रदर्शन करना जानता है, नीतिगत मुद्दों पर ऐतराज जताने का माद्दा उसमे नहीं है । इसमें भाग न लेकर वह संसदीय आचरण के खिलाफ तो जा ही रहा है, साथ ही उसने यह भी जता दिया कि प्रदेश को स्वर्णिम बनाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं ।

ऐसा भी नहीं है कि यह कोई पहला मौका हो । इससे पहले भी कई मौकों पर विपक्ष ने अपना गैर जिम्मेदारानापन दिखाया है । वह सदन के भीतर गंभीर विरोध की बजाए पता नहीं क्यों उथले तौर पर बाहर विरोध का परचम उठाता है । हो सकता है उसे म.प्र.विधानसभा की विश्वसनीयता पर ही भरोसा न हो लेकिन ऐसा हो तो भी उसे ऐसे सदन के भीतर रहकर तमाम सुख-सुविधाओं का उपयोग करने की बजाए सडक पर रहकर ही अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ।

यह बहु प्रचारित सत्र ११ से १५ मई तक आहूत है । इसका एजेंडा भी तय हो चुका है । जिसके तहत सदन में इस बात पर चर्चा होना है कि अपने प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के लिए क्या जतन किए जा सकते हैं ? इस बारे में सदन के भीतर खुले दिमाग से विचार किया जाना है । विपक्ष को इसमें अगर संदेह है भी तो उसे सदन के अंदर जाकर पहले यह देख तो लेना था कि सरकार की कथनी और करना में क्या कोई भेद है या जो उसने बार-बार कहा है उस पर कायम है । उसे लगता कि सरकार केवल नौटंकी कर रही है तो वह सदन के भीतर भी सरकार को बेनकाब कर सकती थी और बाहर भी । विपक्ष हरदम सत्ता पक्ष की नीयत पर संदेह करे और खुद को सत्यवादी हरिशचंद्र माने तो माफ करना ,ऐसी कोई बात तो अब किसी दल के साथ नहीं है । फिर यह भी कोई तरीका नहीं है कि किसी एक मुद्दे पर वे सरकार की समूची नीयत पर सवाल खडे कर दें । यदि प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर नजर डालें तो शिवराजसिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश में ऐसी कोई अराजकता तो नहीं मच गई कि विपक्ष बावरा भूत हो जाए और सदन के बाहर-भीतर ऐसा हंगामा खडा कर दे कि सरकार का सांस लेना ही मुश्किल हो जाए । यदि इस वक्त प्रदेश में कोई चमत्कार नहीं हो रहा तो ऐसा कोई तूफान भी नहीं मचा हुआ है कि विपक्ष को गोवर्धन पर्वत उठा लेना पडे । म.प्र. में विपक्ष में या तो कांग्रेस रहती है या भाजपा । दोनों राष्ट्रीय दल हैं और दोनों से ही यह उम्मीद की जा सकती है कि वे न्यूनतम संजीदापन तो जरूर बरतेंगे । इस वक्त प्रदेश में कांग्रेस के हाथ में विपक्ष की कमान है और केंद्र में कांग्रेसनीत सरकार है तो यह स्वाभाविक अपेक्षा हो जाती है कि वह प्रदेश में संजीदा भूमिका निभाएगी और कहीं से कहीं तक यह संदेश नहीं देगी कि वह केंद्र में होने का फायदा राज्य की सरकार को अस्थिर या असहयोग से करना चाहती है । मौजूदा दौर की बात करें तो यह चिंतन का मुद्दा है कि कांग्रेस क्यों कर सदन की उपेक्षा कर रही है ? जबकि यह एक मौका है जब वह प्रदेश की अवाम के हक में अपने बेशकीमती सुझाव सदन में दे सकती है । सरकार ने खुले दिल से उसे यह न्यौता दिया है कि वह आए और अपने बहूमूल्य सुझाव पेश करे । इतना ही नहीं तो उसने तो विपक्ष की मंशा भापकर यहां तक व्यवस्था दे दी कि वह चाहे तो अपने लिखित सुझाव ही भिजवा दे ताकि उन पर विचार किया जा सके। इस पूरे मामले में सबसे उल्लेखनीय बात तो यह है कि मुट्ठी भर कांग्रेस विधायकों के इरादे जानकर ही मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने समय रहते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर यह दरख्वास्त कर ली थी कि वे अपने विधायकों को सदन में उपस्थित रहने के लिए निर्देशित करें । पता नहीं संसदीय परंपरा निभाने में कांग्रेस को क्यों ऐतराज हो रहा है ?

वैसे कुछ अरसे से यह सिलसिला -सा चल पडा है कि जब सत्ताधारी दल किसी जन हित के मुद्दे पर वाहवाही लूटने की ओर अग्रसर होता दिखे तो उसकी टांग खींच लो । तब विपक्ष सारे काम छोडकर,सारे कारण छोडकर,सारे तर्क किनारे कर सिर्फ विरोध का राग अलापना शुरू कर देता है । इसका पहला और अंतिम खामियाजा जनता को ही भुगतना पडता है । वह सदन के भीतर किसी स्वस्थ बहस से वंचित रह जाती है । ऐसे में लोकतंत्र का जो बडा नुकसान है वह यह कि सत्ता पक्ष स्वच्छंदता की ओर निरंकुशता की ओर तानाशाही की ओर बढ जाता है जिसका नुकसान जनता को भी होता है और लोकतंत्र का भी होता है । यह अगर मान लें कि भाजपा सरकार स्वर्णिम म.प्र. के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं करने वाली । यह भी मान लें कि यह भाजपा सरकार का एक राजनीतिक शिगूफा है । तब भी कांग्रेस की यह जिम्मेदारी थी कि वह सदन के भीतर और बाहर उस पर बहस करती और यह साबित करती कि किस तरह सरकार लोगों को या जनता को भरमा रही है । लेकिन यदि विपक्ष यह नहीं कर पाया तो इसका मतलब साफ है कि वह इस मुद्दे पर विरोध लायक मुद्दो ही नहीं जुटा पा रहा । इसे यूं भी कह सकते है कि विपक्ष के पास इस समय अपने प्रदेश को स्वर्णिम बनाने लायक कोई मुद्दे ,कोई सुझाव ही नहीं है ?

तब भला वे किस मुंह से सहन के भीतर जाकर खडे होते ? विपक्ष ने बेहद सतही तौर पर यह कहा है कि इस सरकार के राज में बेहद अराजकता है,भ्रष्टाचार है । इसलिए वे सत्र का बहिष्कार कर रहे हैं । ऐसी क्या अराजकता और भ्रष्टाचार है इसकी कोई विगत वे नहीं दे पाए । याने कुल मिलाकर वे केवल जबानी जमा खर्च ही करना जानते हैं । यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रदेश में आज एक सक्षम और समझदार विपक्ष की बेहद कमी है । वह न तो सदन के भीतर और न ही सडक पर जनता की आवाज बुलंद करने में सक्षम है ।

रमण रावल